

प्रेषक,

के0 एल0 मीना  
सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- उपाध्यक्ष,  
गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी तथा मुरादाबाद,  
विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 14 अगस्त, 2006

विषय : उत्तर प्रदेश में हाई-टेक टाउनशिप का विकास करने के लिए निजी पूँजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम का चयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2712/8-1-05 दिनांक 21 मई, 2005 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च स्तरीय समिति के निर्माण के आधार पर विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम का चयन सम्बन्धित जनपदों में टाउनशिप के विकास हेतु किया जा चुका है। इसी क्रम में राजस्व अनुभाग-13 द्वारा अपने शासनादेश संख्या-यू.ओ.-27/1-13-2006-रा0-13 दिनांक 3-3-2006 द्वारा हाईटेक नीति के अनुरूप इस आशय के निर्देश प्रसारित किये गये हैं कि विकासकर्ता कम्पनी द्वारा भू-अर्जन की समस्त लागत वहन की जायेगी परन्तु इस पैकेज हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित 10 प्रतिशत अर्जन शुल्क में विकासकर्ता कम्पनी को छूट देय होगी।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हाईटेक नीति के अन्तर्गत स्वीकृत योजना हेतु संबंधित विकासकर्ता कम्पनी/कन्सार्शियम के पक्ष में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव जिलाधिकारी को प्रेषित करते समय प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख कर दिया था कि भू-अर्जन का उक्त प्रस्ताव हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित टाउनशिप के विकास हेतु किया जा रहा है।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

के0 एल0 मीना

सचिव

**संख्या-यू0ओ0-129(1)/आठ-1-2006 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त अपर जिलाधिकारी, भूमि अध्याप्ति/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश।
- 7- अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

**शिव जनम चौधरी**

अनु सचिव